प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

21.01.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

" मुख्य समाचार"

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उड़ान योजना के तहत शिमला के संजौली हैलीपोर्ट से चंडीगढ़, कुल्लू व रिकांगपिओ के लिए हवाई सेवाओं का किया शुभारम्भ।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक देशभर में अव्वल।
- केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत प्रदेश की 2 सौ 94 सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप–प्रदेश में विकास कार्य ठप्प–सरकार में आपसी तालमेल की कमी सार्वजनिक रूप से उजागर।
- कुल्लू के मनाली में राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल की धूम–सैंकड़ों महिलाओं ने पारम्परिक वेशभूषा में महानाटी में लिया भाग।

हैलीकॉप्टर सेवा

राजधानी शिमला के संजौली हैलीपोर्ट से उड़ान योजना के तहत आज से चंड़ीगढ़, कुल्लू और रिकांगपिओ के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रिकांगपिओ के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवाओं का शुभांरभ किया। हैलीकॉप्टर का किराया संजौली से कुल्लू 3 हजार 5 सौ रूपए प्रति यात्री, रिकांगपिओ के लिए 4 हजार रूपए जबकि चंडीगढ़ के लिए 3 हजार एक सौ 69 रूपए प्रति यात्री निर्धारित किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता.....

***वीओ–––केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आज से शिमला के संजौली हैलीपोर्ट से चंड़ीगढ़, कुल्लू और रिकांगपिओ के लिए रोजाना हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू हो गई हैं। इसके अलावा, चंडीगढ़ से संजौली हेलीपोर्ट के बीच सप्ताह में तीन दिन, सोमवार, शुक्रवार और शनिवार हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके शुभारम्भ अवसर पर कहा कि हैलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होने से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के समय की बचत भी होगी। गौरतलब है कि उड़ान योजना के तहत यह सेवाएं शुरू की गई हैं जिसके अंतर्गत हेली टेक्सी सेवा के संचालन का 80 फीसदी खर्च केंद्र और 20 फीसदी खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी।***

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की पहली पोषण नीति बनाएगी, ताकि लोगों को समग्र रूप से लाभ मिल सके। शिमला में आज स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले राज्य में पोषण और खाद्य परीक्षण से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा और नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिले के बद्दी में नई प्रयोगशालाएं खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

पुरस्कार

प्रधानमत्री फसल बीमा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने को–ऑपरेटिव बैंक मध्यम राज्य श्रेणी में खरीफ–2024 और रबी 2024–25 के दौरान उत्कृष्ट कार्यान्वयन में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। इस संबंध में केन्द्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल करने पर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को बधाई देते हुए कहा कि बैंक किसानों के हित में

विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा किसानों व बागवानों के कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

विक्रमादित्य सिंह

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2025–26 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–4 के तहत हिमाचल प्रदेश में 2 सौ 94 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि इसकी कुल लागत 2 हजार 2 सौ 47 करोड़ 24 लाख रूपए है। उन्होंने बताया कि इस राशि में से 2 हजार 19 करोड़ 70 लाख रूपए ग्रामीण विकास मंत्रालय जबकि 2 सौ 27 करोड़ 54 लाख रूपए की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन स्वीकृत परियोजनाओं से राज्य के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्र में सड़क सम्पर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा। लोक निर्माण मंत्री ने इसके लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया है।

विधानसभा अध्यक्ष

प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्तम्भ जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन अवसर पर आज जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही विषय पर अपने सम्बोधन में उन्होंने ये बात कही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है और शासन करने की शक्तियां जनता से ही निकलती हैं। प्रदेश विधानसभा का उल्लेख करते हुए कुलदीप पठानिया ने कहा कि उसकी अपनी एक उच्च परम्परा व गरिमा है।

जयराम ठाकुर

पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में विकास कार्य ठप्प हैं और सरकार जन समस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। धर्मशाला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार में आपसी तालमेल की कमी है और मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर उप–मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ मंत्री सार्वजनिक रूप से प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं जिससे कांग्रेस की आपसी कलह उजागर हो चुकी है।

जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर डिजास्टर एक्ट का सहारा लेकर पंचायत चुनावों को टालने का आरोप भी लगाया।

***पंचायत के चुनाव को लेकर के हम पहले दिन से कह रहे थे कि चुनाव समय से होने चाहिए और जो डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लगा के रखा है, सही मायने में डिजास्टर के प्रभावित इलाके में काम तो हो नहीं रहा है। वो सिर्फ एक ही बात को लेकर डिजास्टर एक्ट का हवाला दिया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव को टालने का एक रास्ता, एक जरिया निकल पाए। तो ये मैं ये समझता हूं कि ये उचित नहीं है।***